प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 33 वर्ष 2005

याचिकाकर्ता सूर्य कुमार तिवारी

बनाम

उत्तरदाता: छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थिति

श्री प्रमोद वर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा श्री सुमित वर्मा, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।

श्री विनय हरित, उप. महाधिवक्ता / उत्तरवादी 1 और 3 के लिए श्री सूर्यकांत मिश्रा

मौखिक निर्णय

16.07.2010

आई.एम. कुद्दुसी, न्यायाधीश

सुना.

2. याचिकाकर्ता, जो मध्य प्रदेश और कलकत्ता उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, को 24.09.2003 के आदेश द्वारा 3 वर्ष की अवधि के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नामित किया गया था। 3 वर्ष की अवधि 23.09.2006 को समाप्त होनी थी। हालाँकि,उत्तरवादी संख्या 1 ने उत्तरवादी संख्या 2 के परामर्श से छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

नियम 2002 (संक्षेप में नियम, 2002) के नियम 5 में संशोधन किया, जिसकी सूचना 4.12.2004 की अधिसूचना द्वारा दी गई, जिसके परिणामस्वरूप 24.09.2003 का नियुक्ति आदेश वापस ले लिया गया। व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने उक्त नियम के नियम 5 में संशोधन को चुनौती देते हुए यह रिट याचिका दायर की है। साथ ही दिनांक 04.01.2005 का आक्षेपित आदेश, जिसके द्वारा दिनांक 24.09.2003 का आदेश वापस ले लिया गया है।

3.नियम, 2002 का संशोधित नियम 5 इस प्रकार है:

> "राज्य प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष, चाहे वह उच्च न्यायालय का सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो, राज्यपाल की इच्छा पर्यन्त पद धारण करेगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपरोक्त संशोधन के मद्देनजर, दिनांक 04.01.2005 के आदेश द्वारा, उत्तरवादी क्रमांक 1 द्वारा याचिकाकर्ता की नियुक्ति आदेश को वापस ले लिया गया। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता को छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के पद से हटना पड़ा।

4.विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रमोद वर्मा ने तर्क दिया है कि छत्तीसगढ़ विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (संक्षेप में अधिनियम, 1987) के अनुसार किया गया है और नियम 2002 भी इसी अधिनियम के अनुसार विरचित किए गए है। हैं। उन्होंने नियम 2002 के असंशोधित नियम 5 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है और तर्क दिया है कि कार्यकारी अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष की अवधि के लिए निर्धारित किया गया है, जिसके नवीनीकरण का प्रावधान है। हालाँकि राज्य/ उत्तरवादी क्रमांक 1 ने उच्च न्यायालय के मुख्य

न्यायाधीश के परामर्श से, नियम 2002 के नियम 5 में संशोधन करके कार्यकारी अध्यक्ष के कार्यकाल को राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त सुनिश्चित कर दिया है। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता का नियुक्ति आदेश वापस ले लिया गया। दिनांक 04.01.2005 का आक्षेपित आदेश संवैधानिक प्रावधानों और उपरोक्त अधिनियम, 1987 का उल्लंघन है।

5.संविधान का अनुच्छेद 310 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों के कार्यकाल का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 310 का खंड (1) यहाँ सुसंगत है और नीचे उद्धृत है:

"इस संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से उपबंधित के सिवाय, प्रत्येक व्यक्ति जो रक्षा सेवा या संघ की सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है या रक्षा से संबंधित कोई पद या संघ के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करता है और प्रत्येक व्यक्ति जो किसी राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है या किसी राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है, राज्यपाल प्रसादपर्यन्त पद धारण करता है।"

संविधान के अनुच्छेद 310(i) के अवलोकन से पता चलता है कि संघ या राज्य में सेवारत व्यक्तियों का कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रपति या राज्यपाल, जैसा भी हो, की इच्छा पर निर्भर करता है। यहाँ तक कि, 1987 के अधिनियम में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के कार्यकाल का भी कोई उल्लेख नहीं है। अधिनियम, 1987 की धारा 6 की उपधारा (2) यहाँ अधिक सुसंगत है और नीचे उद्धृत है:

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(2) राज्य प्राधिकरण में निम्नलिखित शामिल होंगे -

(क) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो मुख्य संरक्षक होगा;

(ख) उच्च न्यायालय का सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जिसे राज्यपाल द्वारा राज्य के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से नामित किया जाएगा, जो कार्यकारी अध्यक्ष होगा।

(ग) ऐसे अन्य सदस्य, जिनके पास ऐसा अनुभव और योग्यताएं हों, जो राज्य सरकार 'द्वारा' निर्धारित की जाएं, जिन्हें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से उस सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यदि हम अधिनियम, 1987 की धारा 6(2) के साथ अनुच्छेद 310(1) के प्रावधानों पर गौर करें तो यह पता चलता है कि किसी प्राधिकारी के पद की विशिष्ट अवधि का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन प्राधिकारी का कार्यकाल असंशोधित नियम, 2002 के नियम 5 में निर्धारित किया गया है, जिसे दिनांक 04.12.2004 की अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया है, जो संविधान के अनुच्छेद 310 के खंड (i) के संवैधानिक प्रावधानों के साथ असंगत है.

6. नियमों में संशोधन करना राज्य का अधिकार क्षेत्र है, जिसे संविधान की भावना के विरुद्ध नहीं कहा जा सकता, क्योंकि संविधान में ही, जैसा कि ऊपर उद्धृत है, अनुच्छेद 310 में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी विशिष्ट सेवा का सदस्य है और संघ या राज्य के अधीन किसी विशिष्ट पद पर आसीन है, राष्ट्रपति या राज्यपाल, जैसी भी स्थिति हो, के प्रसादपर्यन्त उस पद पर बना रहेगा। अतः, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा

प्राधिकरण नियम 2002 के नियम 5 में संशोधन करते हुए किए गए संशोधन अनुच्छेद 310 के खंड (1) के अनुरूप हैं और यह नहीं कहा जा सकता कि यह संविधान के अधिकारातीत है। इसके अलावा, तीन वर्ष का कार्यकाल दिया गया था। याचिकाकर्ता के संबंध में दिनांक 24.9.2003 का नियुक्ति आदेश, जो कि 23.09.2006 को स्वतः ही समाप्त हो जाता यदि वह कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बने रहते और इस प्रकार, जैसा कि प्रार्थना की गई है, इस स्तर पर अर्थात वर्ष 2010 में कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता।

7. उपरोक्त के अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ के मामले में 2007 में 4 एससीसी 353 में रिपोर्ट दी थी जिसमें राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रमुख के रूप में सेवानिवृत्त न्यायाधीश को रखने की प्रथा की निंदा करते हुए कहा था कि सामान्यतः कार्यकारी अध्यक्ष उच्च न्यायालय का कार्यरत न्यायाधीश होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 6(2) के प्रावधानों पर चर्चा के बाद आगे अभिनिर्धारित किया कि राज्य स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष का पद बहुत महत्वपूर्ण है। एक कार्यरत न्यायाधीश एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की तुलना में कहीं बेहतर व्यक्ति होगा और वह अपनी शक्तियों का अधिक प्रभावी ढंग से प्रयोग कर सकता है। चूंकि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का प्रमुख भारत का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का प्रमुख जिला न्यायाधीश होना चाहिए, इसलिए अधिनियम की योजना को इस प्रकार समझा जाना चाहिए कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का प्रमुख भी उच्च न्यायालय का कार्यरत

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

न्यायाधीश होना चाहिए (जोर दिया गया है)। अनुच्छेद 7 और 11 भी यहाँ सुसंगत हैं और नीचे उद्धृत हैं:

"7. कुछ मामलों में, पहले एक कार्यरत न्यायाधीश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे। हमें ऐसा कोई कारण नहीं मिला कि कार्यरत न्यायाधीश की नियुक्ति की लंबे समय से चली आ रही प्रथा से विचलन क्यों किया गया।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है।

"11. कुछ राज्यों में सेवानिवृत्त न्यायाधीश कुछ समय से कार्यरत हैं। संबंधित राज्य सरकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से मामले पर पुनर्विचार करें और चार महीने की अवधि के भीतर आवश्यक कार्रवाई करें।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि कोई भी याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि आक्षेपित आदेश पारित करके याचिकाकर्ता को हटाने का कोई कारण नहीं बताया गया है। इस संबंध में, राज्य द्वारा दाखिल जवाबदावा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है, जिसमें स्पष्ट रूप से संकेत दिया गया है कि सरकार का आशय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से एक कार्यरत न्यायाधीश की नियुक्ति करने का था ताकि उन पर वित्तीय दायित्व कम हो सके। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि कोई कारण नहीं बताया गया है और इसलिए, याचिकाकर्ता को हटाने के वाद को खारिज नहीं किया जा सकता।

09.राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य बनाम संजीव उर्फ बिट्टू के मामले में,

जो एआईआर 2005 एस.सी. 2080 में प्रकाशित की गई है,जिसमें है, सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है। कि न्यायालय कार्यपालिका के प्रशासनिक नीतिगत निर्णयों में तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकते जब तक कि वे मनमाने, तर्कहीन या प्रक्रियागत अनुचित न लगें। इनमें से कोई भी तथ्य इस मामले में सिद्ध नहीं हो सका। उक्त निर्णय का पैरा 15 नीचे उद्धृत है:

"15. निर्धारण के लिए आवश्यक बिंदुओं में से एक प्रशासनिक निर्णयों के मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप की गुंजाइश है। प्रशासनिक कार्रवाई को व्यापक क्षेत्र के लिए संदर्भित किया जा सकता है।सरकारी गतिविधियाँ जिनमें शक्ति के भंडार कार्यकारी, अर्ध-विधायी और अर्ध-न्यायिक प्रकृति के हर प्रकार के वैधानिक कार्य कर सकते हैं। यह सामान्य कानून है कि शक्ति का प्रयोग,चाहे विधायी हो या प्रशासनिक, अपास्त कर दिया जाएगा यदि ऐसी शक्ति के प्रयोग में स्पष्ट त्रुटि है या शक्ति का प्रयोग स्पष्ट रूप से मनमाना है (देखें यू.पी. राज्य और अन्य बनाम रेणुसागर पावर कंपनी और अन्य (एआईआर 1988 एससी 1737)। एक समय इंग्लैंड में पारंपरिक दृष्टिकोण यह था कि कार्यपालिका जवाबदेह नहीं थी जहां इसकी कार्रवाई विशेषाधिकार शक्ति के प्रयोग के कारण थी। प्रोफेसर डी स्मि ने अपने क्लासिकल कार्य "प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा: चौथा संस्करण, पृष्ठ 285-287 पर अपनी संक्षिप्त भाषा में कानूनी स्थिति बताई है जिस प्राधिकरण को विवेकाधिकार दिया गया है, उसे उस विवेकाधिकार का प्रयोग करने के लिए बाध्य किया जा सकता है, लेकिन किसी विशेष

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

तरीके से उसका प्रयोग करने के लिए नहीं। सामान्य तौर पर, विवेकाधिकार का प्रयोग केवल उस प्राधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए जिसे वह सौंपा गया है। उस प्राधिकरण को अपने समक्ष आने वाले मामले पर ईमानदारी से विचार करना चाहिए;

उसे किसी अन्य निकाय के निर्देशों के तहत कार्य नहीं करना चाहिए या प्रत्येक व्यक्तिगत मामले मे विवेकाधिकार का प्रयोग करने से स्वयं को अक्षम नहीं करना चाहिए। अपने विवेकाधिकार के कथित प्रयोग में, उसे वह नहीं करना चाहिए जिसे करने से उसे मना किया गया है, न ही उसे वह करना चाहिए जिसे करने के लिए उसे अधिकृत नही किया गया है। उसे सद्भावना से कार्य करना चाहिए, सभी प्रासंगिक विचारों पर विचार करना चाहिए करना चाहिए, सभी प्रासंगिक विचारों पर विचार करना चाहिए और अप्रासंगिक विचारों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, उसे ऐसे उद्देश्यों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए जो उस कानून के अक्षरशः या भावना के विपरीत हों

जो उसे कार्य करने की शक्ति देता है, और उसे मनमाने या स्वेच्छाचारी करने की शक्ति देता है, और उसे मनमाने या स्वेच्छाचारी ढंग से कार्य नहीं करना चाहिए। इन विभिन्न सिद्धांतों को सुविधाजनक रूप से दो मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: **(i)** विवेकाधिकार का प्रयोग न करना,और**(ii)**

विवेकाधिकार का अतिरेक या दुरुपयोग। हालाँकि, ये दोनों वर्ग

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

परस्पर अनन्य नहीं हैं। इस प्रकार, विवेकाधिकार को अनुचित रूप से बाधित किया जा सकता है क्योंकि अप्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखा गया है, और जहाँ कोई प्राधिकारी अपना विवेकाधिकार किसी अन्य निकाय को सौंपता है, वह अधिकार क्षेत्र से बाहर का कार्य करता है।"

10. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के को देखते हुए, रिट याचिका गलत है और इसलिए इसे खारिज किया जाता है।

11. व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जा रहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही /-
आई.एम. कुद्दुसी
न्यायाधीश

सही /-
एन. के. अग्रवाल
न्यायाधीश

अस्वीकरण : हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Mamta Mahilange

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur